SAFALTA CLASS™

An Initiative by अमर उजाला

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

CURRENT AFFAIRS

NEWS OF 3rd & 4th APRIL

4th April 2020 | 8:30 am to 9:15 am

By Sujeet Sir

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Coronavirus toll touches 62; revised testing norms likely

2,653 cases confirmed across country, 647 of which are from Nizamuddin cluster

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

The number of COVID-19 cases continued to rise in the country with 336 new cases reported in the past 24 hours taking the total tally to 2,547, while 18 more deaths were reported, the Union Health Ministry said on Friday.

India has registered 62 deaths due to COVID-19 so far, while 162 patients have been discharged. Nationwide, 66,000 samples have been tested so far, which includes repeat tests on patients to confirm health status.

COVID-19

In the slow lane: Essential commodities being transported on a bullock cart in New Delhi on Friday, amid the lockdown restrictions.

The spectre of a post-COVID-19 world

The pandemic could not have come at a more difficult time; the global order could see major ch

M.K. NARAYANAN

As COVID-19 spreads exponentially across the world, and the figures of those testing positive as also the numbers of deaths keep increasing in near-ge- the human costs keep mounting. Still, it is important to think of what lies ahead.

The COVID-19 pandemic could not have come at a more difficult time. The world was already having to contend with an uncertain economic environment, with industries in turn facing newer challenges such as having to adjust to a shift from cost efficiencies to innovation and breakthrough improvements. Added to this were: a global slowdown, increasing political

GETTY IMAGE/ISTOCKPHOTO

measures to mitigate the economic hardship engendered by the power that it once was, it is hardly in retreat. It is, without doubt, in creasingly disinclined to act as the world's gendarme, as instanced by its retreat from Afghanistan after a dubious accord with the Afghan Taliban, but this was not the end of the road as far as U.S. power was concerned.

Post COVID-19, however, and given that the U.S. is among the countries badly affected by this pandemic, together with existing uncertainties affecting its financia

कोरोना वायरस की त्रासदी से बिखरने लगा है पूरा यूरोप

इटली की शिकायत

जर्मनी ने इटली को मास्क भेजे हैं, उसने फ़्रांस और इटली के कोरोना संक्रमित रोगियों को अपने अस्पतालों में भी भर्ती किया है.

मगर उसने साथ ही इटली, स्पेन, फ़्रांस और दूसरे देशों की ये अपील ठुकरा दी कि कोरोना वायरस की वजह से जो कर्ज़ जन्मा है उसे बराबर बाँटा जाए.

इटली में कइयों को लगता है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है. ठीक वैसा ही जैसा यूरो संकट और प्रवासी संकट के समय हुआ था.

हंगरी में सत्ता हड़पते प्रधानमंत्री

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन अपनी अनुदारवादी लोकतंत्र की नीति के लिए जाने जाते हैं.

इस हफ़्ते उन्होंने लोकतंत्र से भी पल्ला झाड़ लिया और संसद से एक क़ानून पास करवा लिया जिसके बाद वो जब चाहें तब तक सत्ता में रह सकते हैं.

यूरोपीय कमिशन ने बस नाम के लिए सख़्त समझी जाने वाली प्रतिक्रिया दी और इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि यूरोपीय देशों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि कोरोना वायरस के वक़्त बने क़ानून स्थायी नहीं हैं.

न्यू वर्ल्ड साइबर ऑर्डर

पवन दुग्गल यह भी कहते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लोग डरे हुए हैं इसलिए फिलहाल वो निजता के हनन का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं. इस वजह से भारत ही नहीं दुनिया भर में शासकों को ऐसी ताकत मिल रही है जो आगे चलकर जनता के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है और उसके परिणाम बुरे हो सकते हैं.

उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया के परिवेश में देखें तो एक नया वर्ल्ड साइबर ऑर्डर आ रहा है जहां पर सरकारें अपनी शक्तियों को और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं और इस महामारी के आधार पर लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का लाइसेंस ले रही हैं. लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये महामारी सिर्फ़ इंसानों को ख़त्म नहीं करेगी, जब हालात सामान्य होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि उनकी जानकारियों का दुरुपयोग हो रहा है."

वो मानते हैं कि लोगों को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा और अगर उन्हें इस महामारी के ख़त्म होने बाद कानूनी रास्ते भी अपनाने पड़ सकते हैं ताकि वो अपनी निजता और डिजिटल स्वतंत्रता को बचा सकें. क्योंकि ये ट्रेंड दुनिया के कई देशों में है.

कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से एप करेगा सावधान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को मजबूती देने और आम लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने 'आरोग्य सेतु' नामक मोबाइल एप लांच किया है। यह एप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर न सिर्फ यूजर, बल्कि सरकारी एजेंसियों को भी सचेत कर देगा। 'आरोग्य सेतु' गूगल और एपल दोनों प्लेटफॉर्म पर 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत तैयार किया गया है।

तकनीक

- संक्रमित व्यक्ति के वारे में छह फीट दूर से ही कर देगा अलर्ट
- एपल और गूगल दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलव्ध है 'आरोग्य सेतु'

कोरोना संक्रमित से छह फीट की दूरी पर ही यूजर को सावधान कर देगा। यह नोटीफिकेशन भेजकर यूजर को बताएगा कि वह कोरोना संक्रमित व्यक्ति से कितनी दूरी पर है। यदि वह कोरोना पीड़ित व्यक्ति के ज्यादा करीब पहुंचा और उसके भी संक्रमित होने की आशंका हुई तो सरकारी एजेंसियों को भी सूचना दे देगा, ताकि उस

आरोग्य सेतु ऐप

- सरकार ने एक मोबाइल एप लॉन्च किया है. इस एप नाम 'आरोग्य सेतु' (Arogya Setu app) है.

- इस एप की मदद से लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद मिल सकेगी.

- यह एप लोगों को वायरस से संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर सतर्क करेगा.

बीएस-6 ईंधन की कीमत नहीं बढ़ाएंगी ऑयल कंपनियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार की योजना के मुताबिक इस सप्ताह बुधवार से देशभर में सबसे स्वच्छ बीएस-6 मानक वाले ईंधन की बिक्री शुरू हो गई है। बीएस-4 के मुकाबले इस ईंधन के उत्पादन में ज्यादा लागत आने के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने फैसला किया है कि ग्राहकों से ज्यादा कीमत नहीं वसूली

लागत बढ़ने के बावजूद मौजूदा हालात में कीमत नहीं बढ़ाने का फैसला

दरें बढ़ाई हैं, जिससे ये थोड़े महंगे हुए हैं। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत कुछ अन्य राज्यों ने वैट की दरें

माना जा रहा था कि न
पेट्रोल व डीजल पहले
1.50 रुपये तक महंगे हो
फरवरी, 2020 के बाद से
कीमतों में गिरावट का ज
तेल कंपनियों को काफी
इस दौरान अंतरराष्ट्रीय
तेल 64 डॉलर प्रति बैरल
डॉलर प्रति बैरल पर आ
पूरा फायदा कंपनियों ने

BS6

- According to one WHO's measure, India has nine of the world's ten most polluted cities.

- Over the years, the government has taken various **initiatives** to address the issues related to air pollution.

- such as **the National Clean Air Program, tne Pradhan Mantri Ujjwala Yojana and the Bharat Stage-VI (BS-VI) emission norms.**

- The Union Environment Minister has recently announced that the BS-VI emission norms will be implemented from the year 2020, and this will drastically reduce vehicular pollution.

- **The switch to BS-VI vehicles was to happen in 2022 but looking at the poor air condition, the move was advanced by four years.**

- **At present, BS IV and BS III fuels are available across India.**

मौजूदा दवाओं से ही वायरस को मात देने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारतीय वैज्ञानिक भी जुट गए हैं। नई दवा विकसित होने तक वह मौजूदा दवाओं के जरिये ही इसे मात देने की तैयारी में हैं। हालांकि मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ी यह सामान्य प्रक्रिया होती है, जिसमें किसी नई बीमारी के उभरने पर दूसरे रोगों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को उसके उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका फैसला बीमारी के लक्षण और प्रयोगशाला में उसके प्रभाव को देखने के बाद ही लिया जाता है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) ने देश की एक बड़ी निजी दवा कंपनी और आइटी कंपनी की लाइफ साइंस विंग के साथ मिलकर इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।

- दवा के उत्पादन की नई प्रक्रिया विकसित की जा रही, मलेरिया की दवा प्रभावी पाए जाने पर शोध को मिली रफ्तार

में वैज्ञानिक इसके आसपास या इससे मिलती-जुलती दूसरी दवाओं के प्रभावों को देखने में लगे हैं।

सीएसआइआर के मुताबिक कोरोना से लड़ने का यह उसका कोई अकेला प्रयास नहीं है, बल्कि वह इससे निपटने के लिए पांच सूत्रीय एजेंडे पर भी काम कर रहा है। इनमें बीमारी के खतरे और उसकी प्रकृति को समझने के लिए आणविक स्तर पर निगरानी, किफायती जांच किट बनाना, दवा को विकसित करना, अस्पतालों व निजी सुरक्षा उपकरणों का विकास और चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। खास बात यह है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए

अस्सी फीसद लोग मास्क पहने तो वायरस पर लग सकती है लगाम

नई दिल्ली : केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन के कार्यालय का मानना है कि देश की 80 फीसद आबादी मास्क पहनने लगे तो कोरोना महामारी को थामा जा सकता है। सरकार की ओर से मास्क बनाने की एक नियमावली भी जारी की गई है जिसमें जिसमें घर के ही पुराने सूती कपड़े से मास्क बनाने की विधि

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठन है।

- **स्थापना:** सितंबर 1942

- **केंद्र:** नई दिल्ली

- CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा का वित्तपोषण किया जाता है तथा यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है।

- अध्यक्ष: भारत का प्रधानमंत्री (पदेन अध्यक्ष)

- उपाध्यक्ष: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (पदेन उपाध्यक्ष)

मिलों के लिए एथनॉल बना मुसीबत

वजह ▸ लॉकडाउन से पेट्रोल की मांग घटी तो एथनॉल मिश्रण हुआ ठप, शुगर मिलों पर संकट

मिलों के पास भंडारण सुविधा नहीं, ऑयल कंपनियों से मांगी मदद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के विश्वव्यापी प्रकोप से कच्चे तेल के घटते मूल्य और लॉकडाउन से पेट्रोल की मांग कम होने के चलते एथनॉल का मिश्रण ठप हो गया है। एथनॉल बनाने वाली शुगर मिलों की मुश्किलें यह है कि उनके पास एथनॉल भंडारण की सुविधा नहीं है। उन्होंने तेल ऑयल कंपनियों से

प्रतीकात्मक

होने से हालात बिगड़ सकते हैं। जबकि मिलों ने अपने यहां एथनॉल उत्पादन को

एथनॉल की मांग नहीं के बराबर रह गई है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने ऑयल कंपनियों से एथनॉल खरीदने और उसे अपने डिपो में रखने की मांग की है, जिससे मिलों की समस्या का समाधान हो सके।

ऑयल कंपनियों के डिपो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा व पश्चिम बंगाल में हैं। इन तेल डिपो में एथनॉल का भंडारण किया जाता रहा है। इसी के मद्देनजर इस्मा ने सभी ऑयल कंपनियों से आग्रह किया है कि वे शुगर मिलों के एथनॉल तत्काल खरीदें। उनके

कर बताएंगी। उन्होंने बताया कि चालू कैलेंडर ईयर (जनवरी-दिसंबर,2020) के लिए जितने एथनॉल सप्लाई का कांट्रैक्ट किया गया था, उतनी मात्रा में एथनॉल का उत्पादन मिलों ने पहले ही कर दिया है।

वर्ष 2018 में घरेलू ऑयल कंपनियों ने शुगर मिलों से पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के प्रावधान के तहत 314 करोड़ लीटर एथनॉल आपूर्ति का अनुबंध किया था, जबकि वर्ष 2019 में 330 करोड़ लीटर एथनॉल की आपूर्ति का अनुबंध किया। पिछले महीने ऑयल कंपनियों की ओर से 253 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन

- ***What is ethanol ?***

- Ethanol is basically ***alcohol of 99%-plus purity***, which can be used for blending with petrol.

- ***Produced mainly from*** molasses, a byproduct of sugar manufacture.

- ***About Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme:***

- ***Launched*** in 2003 on pilot basis.

- The aim is ***to promote the use of alternative and environmental friendly fuels***.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

- ***Benefits of ethanol blending:***

- Reduction in import dependency.
- Support to agricultural sector.
- Environmental friendly fuel.
- Additional income to farmers.

लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद करेंगे आइआइटी-आइआइएम छात्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइआइटी, एनआइटी और आइआइएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन में फंसे लोगों के 'सहयोग' की पहल की है। छात्रों ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की स्थापना के साथ-साथ 'सहयोग' नाम से मोबाइल एप को भी लांच किया है। इन दोनों माध्यमों से छात्र लोगों की जरूरतों के बारे में सूचनाएं जुटाएंगे और एनजीओ के जरिये जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाएंगे।

'सहयोग' नामक 700 छात्रों के इस स्वयंसेवी समूह का मानना है कि कई गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और सरकारी एजेंसियां लोगों की मदद करना चाहती हैं, लेकिन उन तक जरूरतमंद लोगों की सूचनाएं ही नहीं पहुंच पा रही हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) गुवाहाटी के पीएचडी छात्र विक्रांत सिंह के अनुसार, 'लॉकडाउन के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से जब बड़ी संख्या में लोग पैदल ही अपने गांव लौटने लगे तो कई एनजीओ और सरकारी एजेंसियों ने उन तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सटीक सूचना का अभाव बाधा साबित हुआ। विक्रांत ने कहा, 'हमने देशभर में फैले अलग-अलग 40 एनजीओ से समझौता किया है। अभी हमारी प्राथमिकता में घरों को लौट रहे लोग और बुजुर्ग हैं। हम ऐसे जरूरतमंद लोगों तक खाना, पीने का पानी, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, कपड़े और दवा आदि पहुंचा रहे हैं।'

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) बेंगलुरु के छात्र गौरव सिंह ने बताया कि इस सेवा की शुरुआत तीन दिनों पहले ही की गई है। फिलहाल, इसकी उपलब्धता उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में है जहां 50 समूह सक्रिय हैं। हम स 7 / 14 ओ के सहयोग से देशभर में फंसे लोगों की मदद की कोशिश कर रहे हैं।

देश के संविधान की शपथ लेने वाले पहले जस्टिस बने रजनीश

जेएनएन, जम्मू : जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार किसी जस्टिस ने भारत के संविधान की शपथ लेकर अपना पदभार संभाला है। जस्टिस रजनीश ओसवाल को हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने गुरुवार को शपथ दिलवाई। इसके साथ जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में जजों की संख्या नौ हो गई है। अब तक जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में जजों को जम्मू कश्मीर संविधान की शपथ दिलवाई जाती थी, लेकिन जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जजों को यहां पर भारत के संविधान की शपथ दिलवाई जाएगी।

राज्यसभा के नए सांसदों की अभी नहीं होगी शपथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लॉकडाउन के चलते 37 नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह टाला

लॉकडाउन की वजह से राज्यसभा के नवनिर्वाचित 37 सदस्यों को अभी शपथ नहीं दिलाई जा सकेगी। हालांकि, संसद में

समयसीमा तय नहीं की गई है। नायडू की ओर से नए सदस्यों को संदेश भेजा गया

Third Schedule:

This schedule lists the various forms of oath for holders of various constitutional offices.

Fourth schedule:

Enumerates the allocation of Rajya Sabha seats to States or Union Territories.

Assocham for $120-bn stimulus

RBI rate cut, liquidity infusion only a 'short-term fix,' it says

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI

Industry body Assocham on Thursday urged the government to roll out a $100-$120 billion stimulus package to help revive all sectors of the economy, that has been battered by the COVID-19 outbreak and the subsequent nationwide lockdown.

ASSOCHAM
INDIA

- **Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)**
- ASSOCHAM was established in 1920 by promoter chambers, representing all regions of India. The Association's head office is located in New Delhi.

Dr. Niranjan Hiranandani,
President, ASSOCHAM

Rating downgrades outpace upgrades, says Crisil

Moody's changes banking sector outlook to 'negative'

SPECIAL CORRESPONDENT
MUMBAI

The impact of a slowing economy has started reflecting in rating actions with downgrades (469) outnumbering upgrades (360) in the second half of fiscal 2020, rating agency Crisil said on Thursday.

As a result, the credit ratio has dropped to 0.77 times compared with 1.21 times in the first half. A ratio below

high share of capital market borrowings.

This is because no moratorium has been announced so far for capital market borrowings (such as bonds and commercial paper) and repayments on these will have to be made on time, during a period when collections would be impacted significantly.

Separately, Moody's Investors Service has changed

- **Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL)**
- **India Ratings and Research Pvt Ltd**
- **The Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA)**
- **Credit Analysis and Research Limited (CARE)**

Motor third party, health renewal dates extended

Policy renewals allowed till April 21

SPECIAL CORRESPONDENT
HYDERABAD

Motor third party insurance and health insurance policies whose renewal date falls during the lockdown period (March 25 to April 14) can be renewed till April 21.

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) shared the details of a notification issued in this regard by the Department of Financial Services with insurers. The uate arrangements are made for ease of payment of premium by policyholders during the week following the end of the lockdown period (the last date being April 21)," IRDAI said.

The regulator said such policyholders would be required to pay the renewal premium for the entire period of 12 months from the date it was due, by April 21. It directed the insurers to communicate details to the

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) is an autonomous, statutory body tasked with regulating and promoting the insurance and reinsurance industries in India

It was constituted by the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999,[2] an Act of Parliament passed by the Government of India.[3] The agency's headquarters are in Hyderabad, Telangana, where it moved from Delhi in 2001.

Subhash Chandra Khuntia is Chairman of IRDAI.

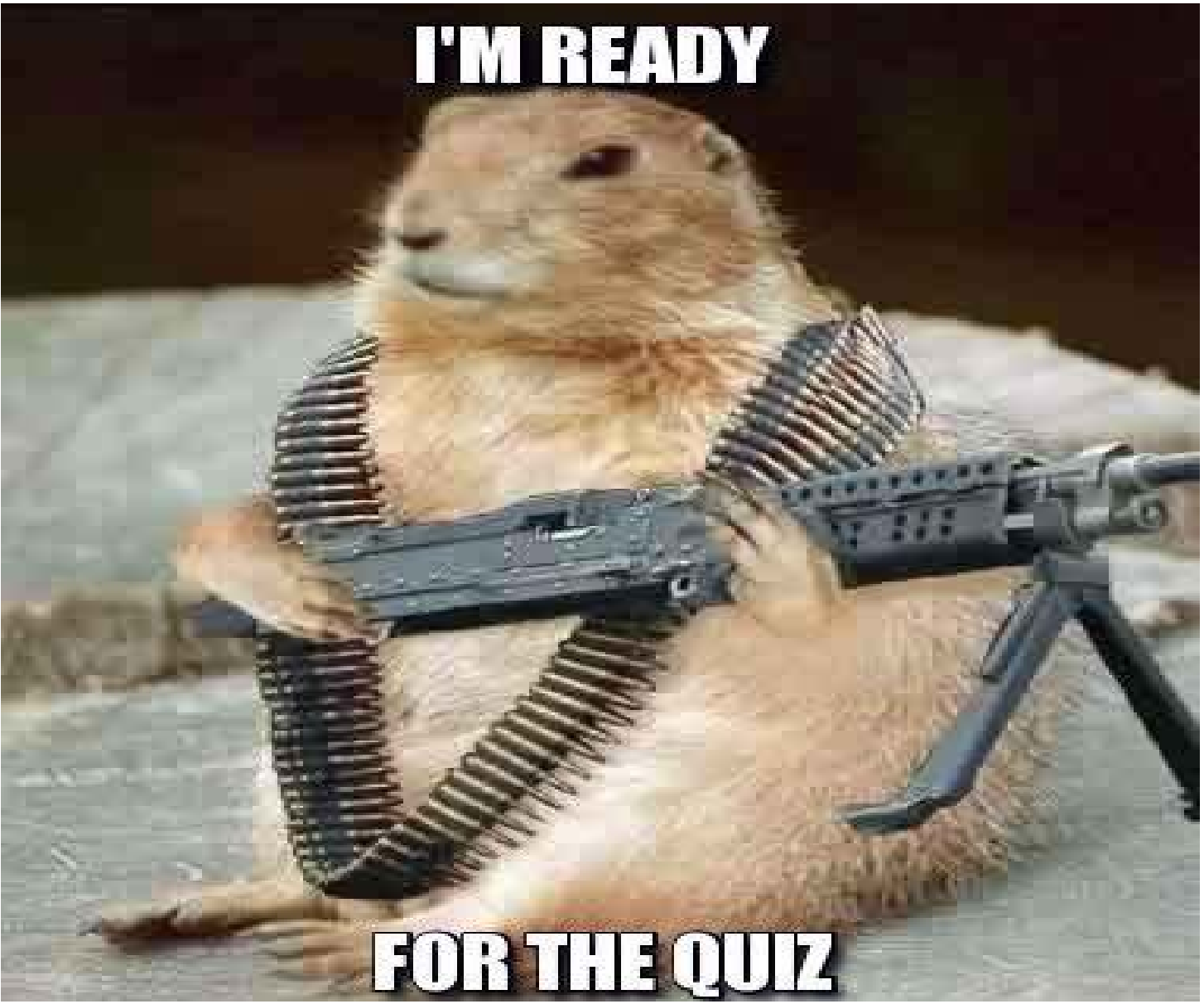

I'M READY
FOR THE QUIZ

Question No: 1

1. DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ?

a. DR. G. Satheesh Reddy

b. K. Sivan

c. N. R. Reddy

d. D. R. Mathur.

Question No: 2

PM - CARE की स्थापना कब की गई ?

a. 26 March 2020

b. 28 March 2020

c. 29 March 2020

d. 2 April 2020

Question No: 3

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में GST Council का वर्णन किया गया ?

a. Art 269-A

b. Art 246-A

c. Art. 279 A

d. Art 280

Question No: 4

Ques 4 PM NRF का full form क्या है ?

(a) Prime Minister's National Relief fund.

(b) Prime Minister's Nehru Revenue fund.

(c) Pandit Nehru National Relief fund.

(d) Prime Minister's National Public Relief fund.

Question No: 5

भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है?

(a) 3 प्रकार

(b) 5 प्रकार

(c) 2 प्रकार

(d) 4 प्रकार

Question No: 6

भारत में अभीतक किस आपातकाल को लागू नही किया गया ?

(a) राष्ट्रीय आपातकाल

(b) वित्तीय आपातकाल

(c) रीजिनल आपातकाल

(d) राष्ट्रपति शासन

Question No: 7

PNB Bank में 1 अप्रैल को किन - किन बैंको को Merge कर दिया गया?

(a) Oriental Bank of Commerce

(b) United Bank of India

(c) Union Bank of India.

(d) A & B. दोनों

Question No: 8

World Trade Organization के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ?

(a) Qu - Dongyu

(b) Roberto Azevedo

(c) Robert White

(d) D- Obrain

Question No: 9

Food and Agriculture Oraganization (FAO) का मुख्यालय कहाँ है?

(a) Geneva
(b) Rome
(c) Newyork
(d) India

Question No: 10

तबलीगी जमात की स्थापना कब हुई ?

(a) 1924

(b) 1926

(c) 1925

(d) 1930

Question No: 11

सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है?

(a) फ्रेंच ओपन (b) आस्ट्रेलियन ओपन

(c) यू. एस. ओपन (d) विंबलडन ओपन

Question No: 12

ICMR का मुख्यालय कहाँ पर है ?

(a) चेन्नई
(b) नई दिल्ली
(c) कलकत्ता
(d) मुम्बई

Don’t Forget to Like / Comment & Share this video

www.Youtube.com/safaltaclass

www.Facebook.com/safaltaclass

www.Instagram.com/safaltaclass

Google Play Store

SAFALTACLASS